

अध्याय 10

बढ़ती मँहगाई और जीवन यापन

आपने लोगों को बढ़ती मँहगाई तथा कीमतों के साथ उनकी बढ़ती प्रेशानियों के बारे में बाते करते सुना होगा लोग बढ़ती हुई कीमतों को लेकर उत्तेजित और चिंतित क्यों रहते हैं। क्या सभी वस्तुओं की कीमतों में बदलाव होता है या कुछ वस्तुओं के ? क्या इसका प्रभाव सभी पर समान रूप से होता है? ऐसे ही कुछ विचारणीय विषयों की चर्चा इस पाठ में हुई है।

परिवार बजट

आपके माता-पिता खेतों में, भवन निर्माण कार्य, सब्जियाँ या अन्य सामग्री बेचकर, दुकानों फैक्ट्री या दफ्तरों में काम करके अपनी आमदनी कमाते हैं। वे इसी आमदनी से घरेलू जरूरतों की आपूर्ति करते हैं। कभी-कभी उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार भी लेना पड़ता है। उनके पास घर चलाने की योजना होती है। वे इसी योजना द्वारा अपनी आमदनी के अनुरूप व्यय करते हैं। आमदनी का इस्तेमाल व्यय ही परिवार बजट कहलाता है।

हर परिवार बजट बनाता है - जो लिखित या मौखिक हो सकता है। आईए, हम सबी मंडी में सबी बेचने वाले परिवार का बजट देखें।

जनवरी 2013 के लिए सुब्बमा का बजट

प्राप्ति	व्यय
माह की कमाई	रु. 3000
रिशेदारों से उधार ली	रु. 2,000
गई राशि	
	स्कूल फीस
	रु. 1500
	डाक्टर की फीस और दवाइयाँ
	रु. 2500
	बस और आटो का खर्च
	रु1500
	बिजली, फोन, तथा अन्य खर्च
	रु. 2000
कुल प्राप्ति	रु. 12,500
	कुल खर्च
	रु.12,500

दी गई सारणी में बाई और सुब्बमा की प्राप्त राशि और दाई और उसके खर्च का विवरण है। उसका व्यय रु.12,500 जो उसकी आमदनी रु.10,000 से अधिक है। इसलिए उसे अपनी लड़की की बीमारी में खर्च हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अपने रिशेदारों से (रु.2500), उधार लेने पड़े। इसी प्रकार हजारों परिवार अपनी आमदनी और खर्च के अनुरूप अपना बजट बनाते हैं।

किस तरह कीमतों में बदलाव परिवार बजट पर असर करता है।

आईए हम फिर से सुब्बम्मा के परिवार का बजट देखेंगे। मान लीजिए अगर उसके मकान मालिक ने घर का किराया रु. 2500 कर दिया और उसी समय बस के किराये और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोत्तरी हो गई तो उसके परिवार को केवल यातायात के लिए रु.2000 प्रतिमाह खर्च करने होंगे। नयी कीमतों के चलते अब उसका जीवन यापन भी रु.1000 बढ़ जायेगा। अगर इनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी न हुई तो इनका परिवार कैसे प्रबंध कर सकेगा? उसके पास अगर कोई बचत राशि है तो वह उसका उपयोग कर सकेगा। अगर नहीं तो उसे लाचार होकर अपने मित्रों या रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ेगा और ब्याज के साथ उसकी भरपाई करनी होगी।

मान लीजिए अगर सुब्बम्मा अपने किसी घनिष्ठ रिश्तेदार से कर्ज लेगा तो उसे ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा लेकिन वह महाजन साहूकार से ऋण लेगा तो उसे उसका ब्याज भी चुकाना होगा। अगर वह $\frac{3}{100}$ या 3% प्रतिमाह हो तो रु.75 ब्याज के हर महीने जोड़े जायेंगे। अगर सुब्बम्मा का परिवार इस कर्ज को ४८ महीनों के बाद चुकायेगा तो उन्हें रु.2500 के अतिरिक्त रु.450 देने होंगे कुल 2950 होंगे।

अपने बजट को व्यवस्थित करने के लिए ये यातायात खरीदारी तथा फोन के बिल पर नियंत्रण रखते हुए अपनी आमदनी और व्यय का प्रबंध कर सकते हैं। कई वस्तुओं के उपभोग में कमी करने के कारण उनका जीवन स्तर घटने लगेगा। इसका कारण जीवन यापन में बढ़ोत्तरी है। स्थिर आमदनी वाले जैसे पेंशन पाने वाले दैनिक रोजी कमाने वाले, शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर, फेरी वाले, छोटे उद्यमों के कर्मचारी लगातार बढ़ती हुई महंगाई के उपरांत अधिक प्रभावित होते हैं। जिसे मुद्रा स्थिति कहते हैं। मुद्रास्थिति के दौरान इनकी आमदनी में कोई बदलाव नहीं होता। इसी कारणवश इन्हें बलपूर्वक अपनी उपभोक्ता में कटौती करनी पड़ती है। निम्न जीवन स्तर होने के कारण मुद्रास्थिति भी इनकी उपभोगता को घटाती है, जिससे यह गरीबी में ढकेले जाते हैं।

लोग हमेशा बढ़ती हुई महंगाई के कारण चिंतित रहते हैं क्योंकि बढ़ती कीमतें उपभोग पर असर करती है। बढ़ते पेट्रोल के दाम, बस या आटो रिक्षा के किराया, सब्जी, दूध और अन्य सामग्रियों के दाम, डाक्टर की फीस आदि के कारण अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। स्थिर आमदनी वाले लोग महंगाई के चलते पहले जितनी वस्तुएं भी नहीं खरीद पाते, उन्हें अपने साधन एवं वस्तुओं की कटौती करनी पड़ती है। इससे उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है। सुखी जीवन जीने के लिए उपायें में लायी गयी वस्तुओं तथा सेवाओं द्वारा ही जीवन स्तर निर्धारित किया जाता है।

जीवन स्तर एक परिवार से दूसरे परिवार का, व्यवसाय का, आमदनी का, और देश का भिन्न होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका जैसे देश में किसी व्यक्ति के पास मोटरकार, टी.वी. या मोबाइल फोन को होना उनका उच्च जीवन स्तर नहीं माना जाएगा। लेकिन भारत जैसे देश में ये चीजें किसी व्यक्ति या परिवार के पास हो तो इनका जीवन स्तर उच्च माना जाएगा। बढ़ती कीमतों में हर कोई प्रभावित होता है। कुछ वर्गों में बढ़ती कीमतों के दरों को क्षतिपूरक किया जाता है।

- कल शिक्षक दिवस है। आपके सहपाठी ने आपको चाकलेट तथा बिस्कुट खरीदने के लिए रु.200 देकर बाजार भेजा। एक चाकलेट के पैकेट का दाम रु. 60 है और बिस्कुट का दाम रु.20 अगर आप दो चाकलेट पैकेट खरीदेंगे तो कितने बिस्कुट पैकेट खरीद सकते हैं। आपको कितने रुपये देने होंगे।
- जब आप अपनी कक्षा में लौटेगो तो आपके मित्र तथा सहपाठी आपसे पूछेंगे कि इतने कम पैकेट कम क्यों खरीदे ? उनके दाम बताने पर वे आश्चर्य चकित हो जायेगे। उनमें से कोई यह भी कह सकता है कि पिछले साल हमने चाकलेट के लिए रु.30 और बिस्कुट के लिए रु.10 दिये थे।
- पिछले एक सप्ताह में क्या हुआ ? दोनों की कीमत बढ़ गई और उसी रु.200 में आपने थोड़ी सामग्री खरीदी।
- मान लीजिए अगर आपके अध्यापक ने बिस्कुट और चाकलेट दोनों के 5 पैकेट इस वर्ष भी खरीदने के लिए कहे तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा।
 - 5 पैकेट चाकलेट के लिए= रु.._____
 - 5 पैकेट बिस्कुट के लिए= रु.._____
 - आप कुल कितने पैसे देंगे= रु._____
 - पिछले वर्ष की तुलना में आपको और कितना अधिक देना होगा ?
- निर्धारित वस्तुओं और सेवाओं को पैसे के द्वारा खरीदना धन की क्रय क्षमता कहलाता है। मुद्रा स्थिति के दौरान आय तथा क्रय क्षमता घट जाती है। उपरोक्त उदाहरण के अनुसार पिछले वर्ष रु.200 पाँच वस्तुओं के लिए दिये गए। लेकिन आज इन्ही वस्तुओं की खरीददारी के लिए आपको अधिक धनराशि चुकानी होगी या आपको कम वस्तुएं खरीदनी होगी। जैसे :
- पिछले वर्ष रु. 200 = 5 पैकेट चाकलेट + 5 पैकेट बिस्कुट
- इस वर्ष रु.200 = 2 पैकेट चाकलेट+ 4 पैकेट बिस्कुट
- दूसरे शब्दों में क्रय शक्ति रु.200 का मूल्य घटा क्योंकि कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण दोनों वस्तुएं उन्हीं रुपयों में कम खरीदनी होगी।

- केन्द्र और राज्य सरकारी कार्यालयों में कुछ संस्थाओं में लोगों को दैनिक भत्ता नामक अधिक भुगतान मिलता है। जब कीमतों में निश्चित प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है तो उनका वेतन भी बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार द्वारा मिलने वाला उनका दैनिक भत्ता भी बढ़ जाता है तथा मुद्रास्थिति के साथ-साथ उनकी आय भी बढ़ेगी।
- कारोबार गतिविधियाँ करने वाले लोग बिक्री के समान की कीमते बढ़ाकर उच्च जीवन स्तर पुनः प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अगर चीनी का दाम बढ़ता है तो मिठाई वाले और चाय वाले मिठाई और चाय का दाम बढ़ा देंगे।
- सेवा करने वाले लोग जैसे ड्राई क्लीनर्ज़, नाई, वकील या डाक्टर भी कीमतों के बढ़ने पर अपना शुल्क बढ़ा देते हैं। वह अपने ग्राहकों, मुद्राकिलों या रोगियों से अधिक फीस लेते हैं।
- निगमित कंपनियों में काम करने वाले, अत्याधुनिक धनी और संपन्न व्यक्ति कीमतों में बढ़ोत्तरी से प्रभावित नहीं होते।

जरूरी वस्तुओं की कीमतों की बढ़ोत्तरी में हर कर्मचारी को क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं होती इष्टांत खेतीहर मजदूर, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, फैक्टरी कर्मचारी कीमतों के बढ़ने पर वेतन बढ़ाने के मांग करते हैं। कभी-कभी अधिक वेतन के लिए विवश किया जाता है। ऐसे समय पर सरकार हस्तक्षेप करती है और मालिकों तथा कर्मचारियों से बातचीत करके इनके बीच समझौता कराते हुए वेतन निर्धारित करती है। कीमत में जरूरी बदलाव और मालिकों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन निर्धारित करने के लिए सरकार ही बहुत सारे व्यवसायों की नित्यकालिक समय पर पुनरावृत्ति करती है।

मुद्रास्थिति को कैसे मापा जाता है?

इससे पहले भी हमने यह बताया है कि वस्तुओं की कीमत में लगातार बढ़ोत्तरी मुद्रास्थिति कहलाती है। आपने यह ध्यान दिया होगा कि कुछ कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण कुछ कीमते घट जाती है। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन के दाम लगातार घटते जा रहे हैं। तो क्या हम समग्र रूप से यह कह पायेंगे कि देश में मुद्रास्थिति है या नहीं ?

मान लीजिए यदि माचिस के दाम बढ़ते हैं तो क्या इससे आपका जीवन यापन स्तर घटेगा। इसकी तुलना आप बढ़े हुए मकान के किराये, चावल के दाम और पेट्रोल के दाम से कीजिए। मान लीजिए और काम्पैक्ट डिस्क जो कम्प्यूटर के प्रयोग में लाई जाती है के दाम बढ़ेंगे तो क्या इसका प्रभाव एक

शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर के बजट को प्रभावित करेगी या अगर किसी औद्योगिक मशीन की कीमत बढ़ेगी तो अप्रत्यक्ष रूप से यह बहुत सारे लोगों के बजट पर कैसे असर करेगी ?

कुछ वस्तुओं या सेवाओं के नाम लिजिए जो नियमित रूप से आपके परिवार में लायी जाती हैं। उनकी पिछली वर्ष और आज की कीमत पता कीजिए। इनमें क्या अंतर है? आप अपने शिक्षक या माता-पिता की सहायता भी ले सकते हैं।

	वस्तुएँ/सेवाएँ	पिछले वर्ष मूल्य	इस वर्ष मूल्य	अंतर
1.				
2.				
3.				
4.				

मूल्य अनुक्रमणिका सूचकांक

मूल्य अनुक्रमणिका के संदर्भ में कीमत में बदलाव का मापन सांख्यिकी उपकरण की सहायता से किया जाता है। किसी एक वस्तु की कीमत में बदलाव सभी वस्तुओं या सेवाओं को प्रभावित नहीं करती है, तो हम समग्र रूप से कीमतों में बदलाव का मापन कैसे करें? मूल्य अनुक्रमणिका सूचकांक का प्रयोग एक तरीका है, जो इस तरह निर्मित किया जाता है।

पहले वर्ष की सभी वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत जो आधार वर्ष के रूप में निर्धारित की जाती है। उसे 100 संख्या दी जाती है। यदि सभी सेवाओं एवं वस्तुओं के दाम पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत बढ़ जाए तो अगले वर्ष के मूल्य सूचकांक में वह 125 प्रतिशत होगा। अगर अगले वर्ष सभी वस्तुओं की कीमत पिछले वर्ष कीमत में 20 प्रतिशत बढ़ती है तो मूल्य सूचकांक का टिकाव होगा। 150 (20% of 125 + 125 = 150)।

मजदूर इसे एक उदाहरण से समझें। नीचे दी गयी सारणी संस्थाओं द्वारा चुकाये गये चावल और कपास की कीमतों को दर्शाता है। इसे ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के जवाब दीजिए।

वर्ष 2005-2011CE चावल और कपास की कीमत (प्रति किवंटनल पर)						
फसल	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010	2010-2011
चावल	रु.. 600	रु.. 610	रु.. 775	रु.. 880	रु.. 980	रु.. 1030
कपास	रु..1980	रु. 1990	रु.. 2030	रु.. 3000	रु.3000	रु.. 3000

- (i) वर्ष 2005-06 का आधार वर्ष के रूप में लेकर चावल और कपास के अनुक्रमणिका सूचकांक की गणना कीजिए।
- (ii) चावल और कपास की अनुक्रमणिका सूचकांक दर्शाती एक रेखाचित्र बनाइए। वर्षों को X अक्ष पर लिखो। साल दर साल रेखा कैसे ऊपर की ओर बढ़ती है इसकी चर्चा कीजिए।

समय से परे समुच्चय वस्तुओं के योग में बदलाव क्रमानुसार सूचकांक दर्शाते हैं। इन्ही वस्तुओं के योग की तुलना एक वर्ष में करते हैं और अगले वर्ष भी। इस प्रकार मूल्य अनुक्रमणिका सूचकांक एक कालांश से दूसरे कालांश में हुई समुच्चय वस्तुओं की कीमतों के बदलाव प्रतिशत को दर्शाता है। दृष्टांत केलिए इस माह और इस वर्ष के परिवार बजट की तुलना हम पिछले वर्ष और पिछले माह से कर सकते हैं। दोनों वर्षों की कीमतों में अंतर यह दर्शाते हैं कि कितने प्रतिशत एक वर्ष में कीमते बढ़ी हैं।

दो स्थानों की कीमत के स्तर की भी तुलना की जा सकती है। हम तेलंगाणा के कीमत स्तर की तुलना कर्नाटक या महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी कर सकते हैं।

अर्थव्यवस्था में हजारों वस्तुओं और सेवाएँ हैं इसीलिए हमें अनुक्रमणिक सूचकांक में किन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए इसका चयन करना होगा।

उपभोक्ता समूह पर आधारित मूल्य अनुक्रमणिका सूचकांक विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे : थोक मूल्य अनुक्रमणिका, उपभोक्ता मूल्य अनुक्रमणिका, थोक मूल्य अनुक्रमणिका में सभी वस्तुएँ (पूँजीगत वस्तुएँ और उपभोक्ता वस्तुएँ) तथा थोक वस्तुओं की कीमतों में बदलाव सम्मिलित होता है। उपभोक्ता अनुक्रमणिका केवल खुदरा मूल्य के बदलाव का ही मापन करता है। भारत में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता अनुक्रमणिका सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं जैसे :

- a) औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता अनुक्रमणिका सूचकांक
- b) शहरी गैर हस्तकला कर्मचारियों के उपभोक्ता अनुक्रमणिका सूचकांक
- c) कृषि मजदूरों के उपभोक्ता अनुक्रमणिका सूचकांक

इतने अधिक सीपीआई का प्रमुख कारण है कि समान वस्तुओं के समुह का उपभोग कई परिवारों द्वारा नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए शहर एवं नगर के औद्योगिक श्रमिक द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएँ ग्रामीण कृषक मजदूर से भिन्न होती हैं। शारीरिक श्रम न करने वाले या नियोक्ता या कार्यालय, बैंक या आईटी कंपनी में काम करने वाले कृषक श्रमिक से भिन्न वस्तुओं का उपभोग करते हैं।

भारत में CPI (थोक मूल्य सूचकांक) पर मुद्रा स्थिति मापा जाती है। कई CPI का उपयोग सरकारी कर्मचारी को दिए जाने वाले DA के अंकन में या भारतीय सरकारी कानून के अनुसार भारत में निर्धनों की संख्या का अंकन कर प्रचलित उजरत दरों की घोषणा की जाती है। खाद्यान्न वस्तुओं का सी.पी.आई मापन खाद्यान्न महँगाई कहलता है।

CPI की रचना कैसे की जाए ?

चलिए एक साधारण सीपीआई की रचना उन वस्तुओं से करेंगे जो आप खरेलू उपभोग के लिए काम में लेते हैं।

तालिका-3 को लेंगे। उन सभी वस्तुओं की कीमतों को लिखिए जिन्हें आपके अभिभावक पिछले महीने खरीद कर लाए थे। चलिए मान ले कि उन्होंने इतनी ही कीमत की वस्तुएँ इस महीने भी खरीदी हैं। परन्तु इस महीने कीमते बढ़ गई तो वही वस्तुएँ अब अधिक कीमती हो गई।

इस तालिका में हमने चार वस्तुएँ ली हैं और उनकी कीमत वजन भी है, जिसे हमने खरीदा है। दूसरे और तीसरे कालम में हम पिछले महीने की संख्या बता रहे हैं। अब हम वजन से उस कीमत को गुणा

करेंगे, प्रत्येक वस्तु पर जो हमने खर्च की है। चौथे कालम में हमने सभी खर्चों को योग किया है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक						
यह एक सीपीआई की रचना का उदाहरण है। चलिए हम यह मानते हैं कि आपके परिवार ने चावल, प्याज, दाल और गैस सिलेंडर खरीदा है।						
1	2	3	4=2 x 3	5	6	7=5 x 6
वस्तुएँ/सेवाएँ	पिछले महीने कीमत ₹	पिछले नहीं मात्रा	पिछले महीने की कीमत	इस महीने की कीमत	इस महीने का मात्रा	इस महीने का खर्च
1. चावल प्रति कि.ग्रा.	₹ 30	25 कि.ग्रा.	₹ 750	₹ 40	25 कि.ग्रा.	₹ 1000
2. प्याज प्रति कि.ग्रा.	₹ 10	5 कि.ग्रा.	₹ 50	₹ 20	5 कि.ग्रा.	₹ 100
3. दाल प्रति कि.ग्रा.	₹ 75	4 कि.ग्रा.	₹ 300	₹ 85	4 कि.ग्रा.	₹ 340
4. गैस सिलेंडर	₹ 400	1	₹ 400	₹ 410	1	₹ 410
कुल खर्च			₹ 1500	कुल खर्च		₹ 1850

उसी प्रकार पाँचवे कालम में हम इस महीने उन्हीं वस्तुओं की कीमत बता रहे हैं। कालम छः में इस महीने खरीदी गयी वस्तुओं का वजन बता रहे हैं। पिछले महीने की वस्तुओं की कीमत के साथ इन वस्तुओं का वजन भी रखा जाय। कालम सात में फिर से उन वस्तुओं की कीमत को वस्तुओं से गुणा कर दिखा रहे हैं। इस तरह कालम सात में हमें इन महीने में खरीदी गई चार वस्तुओं का खर्च है।

तालिका 3 में आपने क्या देखा? आपके परिवार ने पिछले महीने चार वस्तुएँ ₹1500 में खरीदी। लेकिन वही चार वस्तुएँ इस महीने ₹1850 में खरीदी क्योंकि सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है। पिछले महीने की तुलना में ₹350 की मूल्य वृद्धि हुई है। प्रतिशत के अनुसार $350/1500 * 100 = 23.3\%$.

दूसरे शब्दों में जिस परिवार में पिछले महीने ₹100 खर्च किए थे अब इस महीने 123 खर्च किए। सामान उपभोक्ता परिवारों के बजट पर समान रूप से प्रभाव डालता है। उन्हें 23% मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ता है। सीपीआई भी इसी आधार पर मापा जाता है, जो कि परिवार के बजट पर प्रभाव डालता है। आपके जीविका मूल्य में वृद्धि को यह व्यय दर्शाता है।

यदि औसतन इन चार वस्तुओं की कीमत ₹100 पिछले महीने थी जो कि इस महीने ₹123.3 बढ़ गई है। इसका यह अर्थ हुआ कि इन चार वस्तुओं के मूल्य वृद्धि में 23.3% की वृद्धि हुई।

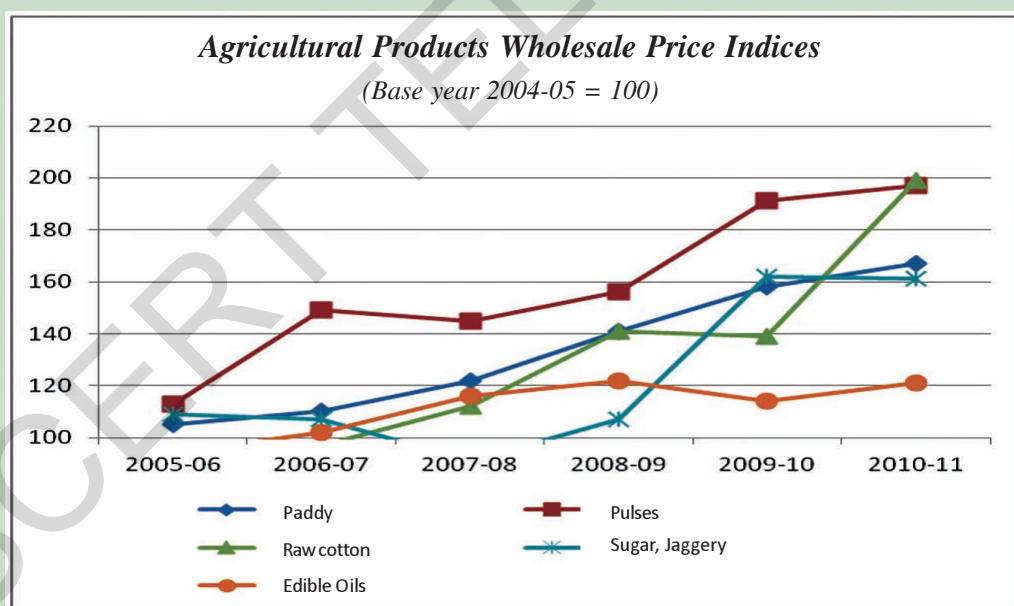
वास्तव में आर्थिक क्षेत्र में हजारों वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और उनकी कीमतें बढ़ती हैं। सरकार इसका मूल्यांकन जो मूल्य वृद्धि समय अंतराल में करती है -अधिकतर प्रति माह या प्रति सप्ताह करती है।

खाद्यान्न मुद्रा स्थिति

2009 से सरकार ने एक नए सूचकांक की स्थापना की है। एफपीआई (Food Price Index) (खाद्यान्न मूल्य सूचकांक) यह सूचकांक भोज्य पदार्थों की कीमतों की वृद्धि को दर्शाता है जो खाद्यान्न मुद्रा स्थिति कहलाता है। एफपीआई में चावल, गेहूं, दाले, सब्जियाँ, शक्कर, दूध, अंडे, मांस, मछली और भोजन बनाने की अन्य वस्तुओं जैसे खाद्य तेल के थोक व्यापार मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। 2011-12 में खाद्य तेल के कीमतों में ऊँची वृद्धि देखी गई। उस वर्ष लगभग 50 प्रतिशत कच्चा पामलेत, सूर्यमूखी, सोयाबीन तेल और रिफाइन्ड पामोलिन भारत में विदेशों से आयात किया गया। जब इन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई जिन देशों से हमने आयात किया था। भारतीय उपभोक्ता को भी उच्च कीमत देनी पड़ी। मूल्य वृद्धि पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। इस पर कई अन्वेषण अध्ययन का आयोजन किया गया है। यह भी देखा गया है कि लोगों के खान-पान में भी परिवर्तन आ गया है। हाल ही में सब्जियाँ, अंडे, मांस और मछली का उपयोग बोझ हो गया है। जब कभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है तो मांग के बढ़ते ही वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। लोग उन्हें अधिक कीमत पर भी खरीदना चाहते हैं। यह उनके नियमित आहार का अंश बन गया है।

वर्तमान में मूल्य वृद्धि

2009-11 मौलिक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। निम्न चित्र को देख कर आप जान सकते हैं। चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर उत्तर दीजिए।



- यदि एक परिवार 20 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से वर्ष 2005-06 में चावल खरीदता है तो उसे अब 2011 में कितने में खरीदना पड़ रहा होगा?
- किस वर्ष में दालों की कीमत में नियमित वृद्धि हुई है?
- कपास की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
- कौन सी वस्तु कम या अधिक स्थिर रही है?

आप इस बारे में जानते ही हैं कि अधिकतर पेट्रोल, डीजल और केरोसीन पेट्रोलियम पदार्थों से बनाया जाता है, जो कि अन्य देशों से आयात किया जाता है। भारत में धातु एवं रसायन की कीमतों में वृद्धि के साथ ही कच्चे पेट्रोलियम की कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। दीर्घ समय के बाद वस्तु एवं सेवा के मूल्यों में साधारण वृद्धि को मुद्रा स्थिति कहते हैं। भारत में इन उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर प्रभाव डालती है।

मूल्य निर्धारण में सरकार की पात्रता

जब सामान्य मुद्रा स्थिति होती है तो थोक मूल्यों में तीव्र वृद्धि होती है जो कि उद्योगपतियों को अधिक प्रभावित करती है। यदि खाद्यान्न मुद्रा स्थिति में वृद्धि हो जाए तो साधारण मनुष्य के जीवन में इसका प्रभाव अधिक होता है। ऊँची मुद्रा स्थिति के समय केवल निम्न आय वाले या निर्धारित आय वाले ही प्रभावित नहीं होते और अधिक गरीब नहीं बनते। अन्य लोग अपनी पूँजी का नियोजन भूमि सोना या अन्य उत्पादित वस्तुओं की खरीदने में करते हैं। लोगों को लगता है कि उनकी मुद्रा की कीमत दिन ब दिन घटती जा रही है।

यह भी माना जाता है कि आधुनिकता एवं समन्वय के आधार पर वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना देश के लिए हितकारी है। यदि वस्तु की कीमत प्रति वर्ष 2-3 प्रतिशत तक बढ़ती है तो यह अच्छे देश की निशानी है, क्यों? यदि उत्पादन कर्ता अपने जीवन स्तर को विकसित करना चाहते हैं तो उनके उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करेंगे। उत्पादन की कीमतों में वृद्धि करता है और अंत में कीमत में। अंत में उपभोक्ता को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। मूल्य वृद्धि का लाभ श्रमिक को होता है जो उन वस्तुओं को बनाते हैं, यह देश के लिए अच्छा माना जाता है।

उसी समय व्यापारी का मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ कमाने का होता है तो वह गैर कानूनी ढंग से मौलिक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर देते हैं। यदि श्रमिकों के वेतन में वृद्धि न की जाए जो स्वयं ही उपभोक्ता होते हैं, वे वस्तुओं को नहीं खरीद सकते। जब यह वस्तुएं आवश्यक बन जाती है जैसे- गेहूँ, चावल, दूध आदि तो उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है।

यह आवश्यक हो जाता है कि व्यापारियों का निर्धारण किया जाय और उन पर पैनी दृष्टि रखी जाय। इस दिशा में सरकार प्राथमिक कदम उठा रही है। आप कृषि के अध्याय को याद कीजिए जिसमें आपने सीखा कि कैसे सरकार के द्वारा किसानों को धान और गेहूँ उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यह योजना केवल किसानों की ही सहायता नहीं करती बल्कि बाजार में धान, गेहूँ के मूल्य निर्धारण में भी उपयोगी है। उसी समय केन्द्रीय एवं प्रादेशिक दोनों स्तरों पर गन्ने की कीमत का निर्धारण सरकार करती है और सहकारी शक्कर मिलों में शक्कर तैयार करवाती है। यह एक प्रकार से बाजार में गन्ने की कीमत को निर्धारित करता है।

आपने कक्षा आठ में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। यह सरकार को महत्वपूर्ण क्रिया कलाप है जो न केवल गरीब लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा का विश्वास दिलाती है बल्कि मौलिक वस्तुओं की कीमतों को भी नियंत्रित करती है। पीडीएस के अंतर्गत सरकार मौलिक वस्तुएँ जैसे गेहूँ, चावल,

शक्कर, खाद्य तेल एवं केरोसीन के वितरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह योजना प्रादेशिक सरकार द्वारा लगभग 4.5 लाख उचित दरों की दुकानों की सहायता से लागू करती है। पीडीएस (PDS) द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत बाजारी मूल्यों से कम होती है। भारत सरकार सहायक मूल्यों या छूट दर चुकाया जाता है। न केवल इन दूकानों से गरीबों को कम कीमत पर वस्तुएँ प्राप्त होती हैं बल्कि यह पद्धति बाजार में बढ़ने वाली कीमतों को नियंत्रित करती है।

संचय को रोकने के लिए और मौलिक वस्तुओं को उचित दरों में रखना और उनकी उपलब्धता सरकार मूल्यों को निर्धारित करती है और व्यापारियों को उन्हीं कीमतों पर बाजार में बेचने पर विवश करती है। जो इन कीमतों का पालन नहीं करता है सरकार विभिन्न कानूनों द्वारा उन्हें दंड देती है। उदाहरण - केरोसीन, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, और पीएनजी जैसी वस्तुओं पर आंशिक या पूर्णतः छूट कर, सरकार देती है।

जब कभी मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत में सभी बैंकों की बैंक है, आर्थिकता पर मुद्रा बहाव को कम कर देती है। यह अन्य बैंकों द्वारा होता है। बैंकों से कम या अधिक या जमाकर्ता को धनराशि कम या ज्यादा निकालने की अनुमति दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की सहायता से जमाकर्ताओं को ब्याज प्रदान करना या उनसे प्राप्त करने पर नियंत्रण करती है। ब्याज दर पर नियंत्रण कर उस धन को देश के पतन में वितरित करती है। धन की कमी से संपूर्ण देश में पतन उत्पन्न करती है। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति कम उपभोग करेगा जो वस्तुओं की मांग में कमी को उत्पन्न करता है और दाम भी कम हो जाते हैं। आरबीआई के द्वारा उठायें गये कदम के प्रभाव को जानने में अभी समय शेष है। जब कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होती है तो आरबीआई (RBI) के लिए कठिनाई हो जाती है।

जब सरकार मुद्रा बहाव में कमी का निर्णय लेती है, यह उच्च आय वालों पर और उपभोक्ता वस्तुओं पर कर की मात्रा बढ़ा दी जाती है। यहाँ सरकार का यह उद्देश्य होता है कि लोगों की खरीदी योग्यता में कमी लाए। जब व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए कम धन होगा तो उनका उपभोग भी कम हो जायेगा जो कि मूल्यों में पतन लाता है।

मौलिक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने में आयात -निर्यात योजना का भी सरकार उपयोग करती है। उदाहरण के लिए यदि खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो उन वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगा दी जाती है या उसकी मात्रा कम कर दी जाती है। जब किसी वस्तु की कमी हो जाती है तो सरकार अन्य देशों से मंगवाती है और सरकारी संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि सहकारी बाजारी भारत संघ लिमिटेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd (NAFED)) और अन्य सहकारी समितियों के द्वारा बाजारी कीमतों से कम में वितरित करती है। जब कभी व्यापारी वस्तुओं का संचय कर कमी पैदा करते हैं तो सरकार वैधानिक तकनीक का उपयोग भी कर सकती है।

मुख्य शब्द

- | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|
| 1. जीवन स्तर | 2. मुद्रास्फीति | 3. उपभोक्ता दर सूची |
| 4. थोक दर सूची | 5. प्रबंधन दर व्यवस्था | |

शिक्षा में सुधार

1. कीमतों को नियमित करने की आवश्यकता क्यों है?
 2. किसी विक्रेता या उत्पादक द्वारा कीमत कैसे तय की जाती है?
 3. जीवनमूल्य और जीवन स्तर में भेद स्पष्ट कीजिए।
 4. मँहगाई बढ़ने का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? और क्यों?
 5. जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो सर्वाधिक लाभ किसको होता है?
 6. थोक दर सूची किस प्रकार उपभोक्ता दर सूची से भिन्न होती है?
 7. आहार मुद्रास्फीति, उपभोक्ता दर सूची से किस प्रकार भिन्न होती है?
 8. CPI के उपयोग के बारे में लिखिए।
 9. CPI मापन में किन पाँच मुद्रों को ध्यान में रखा जाता है?
 10. इस अध्याय का छठा अध्याय पढ़िए और ‘सरकार की दाम नियंत्रण में भूमिका’ के बारे में पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।
- APM किस प्रकार सरकारी आय को प्रभावित करता है?
11. अपने घर में उपयोग की जाने वाली कोई पाँच वस्तुओं का लीजिए और इन पाँच वस्तुओं/सेवाओं के आधार पर उपभोक्ता दर सूचकांक तैयार कीजिए।

1	2	3	4=2 x 3	5	6	7=5 x 6
सामग्री	पिछले माह दाम	पिछले माह खर्च	इस माह दर	इस माह खर्च	इस माह खपत	खर्च
1.	Rs.		Rs.	Rs.		Rs.
2.	Rs.		Rs.	Rs.		Rs.
3.	Rs.		Rs.	Rs.		Rs.
4.	Rs.		Rs.	Rs.		Rs.
5.	Rs.		Rs.	Rs.		Rs.
कुल खर्च				Rs.	कुल खर्च	Rs.
CPI: _____ %						
पिछले माह से इस माह में क्या परिवर्तन हुए? _____						

12. सही या गलत लिखिए।

- (a) मुद्रास्फीति जीवन स्तर को बढ़ाती है []
- (b) रूपये के मूल्य की कीमत खरीदने की क्षमता के परिवर्तन में दिखाई देती है। []
- (c) जीवन यापन में परिवर्तन का निवृत्ति वेतनभोगी जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता []
- (d) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मुद्रास्फीति की क्षतिपूर्ति तनखाह में मँहगाई भत्ता (DA) में वृद्धि से होती है। []
- (e) WPI केवल उपभोक्ता सामग्री में दर परिवर्तन को मापता है। []

13. निम्न तालिका कारखानों के थोक भाव को दर्शाती है। इसके लिए एक आरेख खींचिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- (a) किसका दाम साल भर बढ़ता रहा?
- (b) सूती कपड़े और खाद का दाम धीरे-धीरे बढ़ने का क्या कारण है?

वर्ष	कोयला	सूती कपड़ा	खाद	सीमेंट	इस्पात
2005-06	118	99	102	102	100
2006-07	118	97	104	119	105
2007-08	122	99	106	138	119
2008-09	151	103	107	139	137
2009-10	156	107	108	149	124
2010-11	165	115	117	151	136

14. अपने सुझाव दर्शाते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित देखरेख के लिए अपने तहसीलदार को एक पत्र लिखिए।